

मद्रास राज्य बनाम वी.जी. रो मामला

प्रलिस के लयः

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [मौलिक अधिकार](#), मौलिक अधिकारों पर प्रतबंध

मेन्स के लयः

मौलिक अधिकारों पर प्रतबंध, अधिकारों के प्रतबंध पर तर्कसंगतता का परीक्षण

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

1952 में [सर्वोच्च न्यायालय](#) के नरिणय ने [मौलिक अधिकारों](#) को प्रतबंधित करने वाले कानूनों के लयि तर्कसंगतता की कसौटी स्थापति की ।

- इसने न्यायिक समीक्षा के लयि एक प्रतमान स्थापति कयि तथा यह सुनिश्चित कयि कि नगरिक स्वतंत्रता पर प्रतबंध नषिपक्ष, न्यायसंगत तथा अत्यधिक नहीं होने चाहयि ।

मद्रास राज्य बनाम वी.जी. रो मामला क्या है?

- पृष्ठभूमि:** इस मामले में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1950 को चुनौती दी गई, जिसमें सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था के लयि प्रतिकूल समझे जाने वाले संघों को प्रतबंधित करने का अधिकार दयि, जिसके तहत मद्रास सरकार ने वर्ष 1950 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी पर प्रतबंध लगा दयि ।
 - प्रतबंधित सोसायटी के सदस्य वी.जी. रो ने तर्क दयि कि कानून **अनुच्छेद 19(1)(c) (संघ बनाने का अधिकार)** का उल्लंघन करता है और **अनुच्छेद 19(4)** के तहत अनुचित प्रतबंध लगाता है ।
- सर्वोच्च न्यायालय (SC) का नरिणय:**
 - वर्ष 1952 में, **सर्वोच्च न्यायालय** ने इस कानून को **असंवैधानिक** करार देते हुए नरिणय दयि कि **संघों पर प्रतबंध लगाने में अत्यधिक कार्यकारी वविक** अनुचित था और अनुच्छेद 19(1)(c) का उल्लंघन करता था ।
 - इसमें इस बात पर जोर दयि गया कि प्रतबंध **नषिपक्ष, न्यायसंगत** होने चाहयि तथा अपने उद्देश्य के संबंध में अत्यधिक नहीं होने चाहयि ।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने **उल्लंघन कयि गए अधिकार की प्रकृति**, प्रतबंध का उद्देश्य और सीमा, **संबोधित मुद्दे की आनुपातिकता** और मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर **प्रतबंध की तर्कसंगतता का परीक्षण करने** के लयि एक रूपरेखा तैयार की ।
- महत्त्व:**
 - संवैधानिक न्यायशास्त्र का विकास:** तर्कसंगतता **परीक्षण मूलभूत** बन गया, तथा वकिसति होकर **संरचित आनुपातिकता परीक्षण** के रूप में वकिसति हुआ, जिसका उपयोग आज मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाली राज्य की कार्यवाहियों के मूल्यांकन के लयि कयि जाता है ।
 - आधुनिक वधिक ढाँचे पर प्रभाव:** **वधिविरोध कर्या-कलाप (नवारण) अधिनियम (UAPA), आतंकवादी और वधिवंसक कर्या-कलाप (नवारण) अधिनियम (TADA), और आतंकवाद नवारण अधिनियम (POTA)** जैसे अधिनियमों की इसके तहत जाँच की गई ताकियह सुनिश्चित कयि जा सके कि इनसे **मनमाना रूप से नगरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हो** ।

नोट:

- [1952](#) में, सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय कयि कि **आवागमन और संचार पर प्रतबंध**

